दया चौधरी, जे, के समक्ष

मास्टर भोलु अपने पिता और प्राकृतिक रक्षक/**natural guardian** विनोद कुमार द्वारा -अपीलकर्ता

बनाम

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो-प्रतिवादी

सीआरए-एस संख्या **646**-एसबी, **2018** (ओ एंड एम)

06 जून, **2018**

दण्ड प्रक्रिया संहिता **1973**-खंड **167 (2)**-किशोर न्यायाधीश (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, **2015**-खंड **21** भारतीय दंड संहिता **1860**-खंड **302** कानून के साथ संघर्ष/**conflict in law** में बच्चे द्वारा हत्या-जांच के लिए निर्धारित समय-जब अधिकतम सजा जो लगाई जा सकती है वह आजीवन कारावास है, तो जो भी न्यूनतम सजा हो, खंड **167 (2) Cr.P.C, 1973** के उद्देश्यों के लिए जांच एजेंसी को **90** दिनों का समय उपलब्ध होगा-जांच एजेंसी को जांच पूरी करने के लिए उपलब्ध समय अवधि, कानून के साथ संघर्ष में बच्चे/**conflict in law** के कथित हत्या का अपराध करने के मामले में **90** दिन है न कि **60** दिन।

माना जाता है कि पहले मुद्दे पर विचार किया जाता है, यह इस बात से संबंधित है कि क्या जांच एजेंसी को 60 दिनों या 90 दिनों की अवधि के भीतर चालान दायर करने की आवश्यकता है, ऐसे मामले में जिसमें कानून के साथ संघर्ष/conflict in law में बच्चे द्वारा कथित रूप से हत्या की गई है।अपीलकर्ता विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि चालान प्रस्तुत करने की समय अवधि 60 दिनों की होगी क्योंकि उसका मामला Cr.P.C की खंड/ धारा 167 (2) (a) (ii) के दायरे में आता है। अपीलकर्ता विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि जाँच एजेंसी को 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरा चालान दाखिल करने की आवश्यकता है।आम तौर पर, हत्या के मामले में निर्धारित सजा या तो 'मौत' या 'आजीवन कारावास' होती है।ऐसी स्थिति में, निश्चित रूप से, जांच एजेंसी के पास जांच को समाप्त करने के लिए 90 दिनों की समय अवधि होती है-जिसमें विफल रहने पर, आरोपी खंड 167 (2) के प्रावधानों के अनुसार

वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत लेने के अपने अधिकार का दावा कर सकता है। हालाँकि, यदि कानून के साथ टकराव/conflict in law में कोई बच्चा हत्या के अपराध के लिए मुकदमे का सामना कर रहा है, तो उसे न तो मौत की सजा दी जा सकती है और न ही किशोर न्यायाधीश अधिनियम की खंड 21 के प्रावधानों को देखते हुए रिहाई की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है।

आर. एस. राय, वरिष्ठ अधिवक्ता कुणाल डावर के साथ, मास्टर भोलु के लिए अधिवक्ता उनके पिता और प्राकृतिक रक्षक विनोद कुमार बनाम केंद्रीय ब्यूरो द्वारा से

अपीलकर्ता।

सुमित गोयल, सीबीआई के स्थायी वकील।

शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनुपम सिंगला ने कहा,

दया चौधरी, जे

(1) वर्तमान अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम द्वारा पारित दिनांक 05.02.2018 के विवादित आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन u/s 167 (2)(a)(ii) को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की खंड 2 (33) और 21 के साथ पढ़ा जाता है (संक्षेप में 'किशोर न्याय प्राथमिकी दंड संहिता की खंड 302, शस्त्र अधिनियम, 1954 की खंड 25, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की खंड 12 के तहत दंडनीय अपराध के लिए No. RC-8 (S)/2017/SCIII/नई दिल्ली दिनांक 22.09.2017 मामले में वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत देने के लिए।

(2) संक्षेप में, वर्तमान अपील में मामले के तथ्यों के बारे में बताया गया है कि गुरुग्राम जिले के भोंडसी पुलिस स्टेशन में भा.दं.सं. सी. की खंड 302, शस्त्र अधिनियम की खंड 25, पॉक्सो अधिनियम की खंड 12 और किशोर न्यायाधीश अधिनियम की खंड 75 के तहत FIR /प्राथमिकी No. 250 दिनाक 08.09.2017 दर्ज की गई थी। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की और मामले की जांच को सी. बी. आई. को स्थानांतरित कर दिया और उसके बाद, मामले को प्राथमिकी आर. No.RC-8 (एस)/2017/एस. सी. आई. आई./नई दिल्ली दिनांक 22.09.2017 के रूप में फिर से दर्ज किया गया।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मद्देनजर उक्त प्राथमिकी दर्ज करने के बाद, मामले की जांच सी. बी. आई. द्वारा की गई थी। वर्तमान अपीलकर्ता को सी. बी. आई. द्वारा गिरफ्तार किया गया था और 08.11.2017 पर किशोर न्यायाधीश बोर्ड के समक्ष पेश किया गया था।इसके बाद, किशोर न्यायाधीश बोर्ड द्वारा एक जांच की गई और दिनांक 20.12.2017 के आदेश के अनुसार, यह आदेश दिया गया कि अपीलकर्ता पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है और मामले को बाल न्यायाधीशालय में स्थानांतरित किया जा सकता है।चूँकि किसी भी न्यायालय को विशेष रूप से बाल न्यायालय के रूप में नामित नहीं किया गया था, इसलिए वर्तमान अपीलकर्ता पर किशोर न्याय अधिनियम के तहत एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के लिए मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम के न्यायालय को सौंपा गया था।

अपीलकर्ता की गिरफ्तारी के बाद, उसे अवलोकन गृह में रखा गया था।जब सी. बी. आई. द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर चालान प्रस्तुत नहीं किया गया, तो अपीलकर्ता ने खंड/धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत एक आवेदन दायर किया। अहलमद की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि चालान सी. बी. आई. द्वारा 05.02.2018 पर जमा किया गया था। खंड/धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन को 05.02.2018 दिनांकित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, जो वर्तमान अपील में चुनौती का विषय है।

अपीलकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि 60 दिनों की अवधि 05.01.2018 पर समाप्त हो गई थी और गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिनों की अवधि 04.02.2018 पर समाप्त हो गई थी।चालान 60 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया था और अपीलकर्ता खंड/धारा 167 (2) Cr.P.C के प्रावधानों के अनुसार जमानत का हकदार बन गया था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि विवादित आदेश पारित करते समय, निचली अदालत ने माना है कि चालान दाखिल करने की अवधि 90 दिन थी क्योंकि अपीलकर्ता भा.दं.सं. सी. की खंड 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमे का सामना कर रहा था। जमानत देने के लिए आवेदन 90 वें दिन दायर किया गया था और उस दिन केवल आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया था और अपीलकर्ता जमानत का हकदार नहीं था।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यह भी प्रस्तुत करते हैं कि किशोर न्यायाधीश अधिनियम की खंड 21 के प्रावधानों के अनुसार, चालान दाखिल करने की अवधि 90 दिन थी और 60 दिन नहीं थी क्योंकि मामले में, अपराध मौत की सजा

और आजीवन कारावास से दंडनीय है, तो चालान प्रस्तुत करने की अवधि 90 दिन है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यह भी प्रस्तुत करते हैं कि खंड 167 (2) Cr.P.C के प्रावधान के अनुसार, यह स्पष्ट है कि 90 दिनों की कुल अवधि एक ऐसे अपराध के लिए निर्दिष्ट है जहां अपराध मौत, आजीवन कारावास या 10 साल से कम की अवधि के लिए दंडनीय है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि खंड 5 Cr.P.C. से पता चलता है कि उक्त खंड एक बचत खंड है और इसमें यह प्रावधान है कि इसके विपरीत किसी विशिष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति में में न्यायाधीशालय में कुछ भी किसी विशेष या स्थानीय कानून को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन किशोर न्यायाधीश अधिनियम की खंड 103 के अनुसार, Cr.P.C के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन किया जाना है।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि किशोर न्यायाधीश अधिनियम के तहत लगाई जा सकने वाली सजा को खंड 167 (2) Cr.P.C के तहत जमानत देने के लिए देखा जाना चाहिए। किशोर न्यायाधीश अधिनियम के अनुसार, किशोर द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं की गई है और चालान दायर करने की अवधि 90 दिन नहीं होगी, लेकिन यह 60 दिन होगी।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि जांच एजेंसी-सी. बी. आई. 05.02.2018 तक चालान जमा करने में विफल रही है, जो किशोर को पेश करने की तारीख से 90 वां दिन था अर्थात 08.11.2017।चालान 06.02.2018 पर प्रस्तुत किया गया था, जिसे न्यायालय की संस्थागत शाखा में विधिवत समर्थन दिया गया था।इसका मतलब है कि 90 दिनों की अवधि 05.02.2018 पर समाप्त हो गई थी और अपीलकर्ता खंड 167 (2) Cr.P.C के तहत जमानत का हकदार बन गया था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यह भी प्रस्तुत करते हैं कि चालान 05.02.2018 पर दोपहर 3:30 बजे तक प्रस्तुत नहीं किया गया था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील प्रस्तुत करते हैं कि चालान की प्रस्तुति पर विचार किया जाएगा जब इसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा न कि अहलमद के साथ। अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उनकी दलीलों के समर्थन में।राकेश कुमार पॉल बनाम असम राज्य और राजीव चौधरी बनाम राज्य (एन. सी. टी.) दिल्ली में प्रस्तुत किया गया, निर्णयों पर भरोसा किया है

(3) सी. बी. आई. के विद्वान स्थायी वकील ने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि वर्तमान अपील विचारणीय नहीं है क्योंकि आदेश निचली अदालत द्वारा खंड 167 (2) Cr.P.C के तहत पारित किया गया था

और अपीलकर्ता ने किशोर न्यायाधीश अधिनियम की खंड 101 के तहत वर्तमान अपील दायर की है। किशोर न्यायाधीश अधिनियम के तहत अपील केवल तभी कायम रखी जा सकती है जब उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक आदेश पारित किया जाता है, लेकिन खंड 167 (2) के तहत जमानत को अस्वीकार करने वाले आदेश के खिलाफ अपील का कोई प्रावधान नहीं है। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करता है कि अपीलकर्ता ने पहले किशोर न्यायाधीश बोर्ड द्वारा पारित आदेश को किशोर न्यायाधीश मॉडल नियम, 2016 के नियम 10 (5) के तहत दायर एक आवेदन No. 635/2018 में चुनौती देने के लिए इस अदालत के समक्ष 2018 का आपराधिक संशोधन दायर किया है, जिसे खारिज कर दिया गया था।विद्वान वकील यह भी प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान अपील की सामग्री अपीलकर्ता द्वारा पिछली याचिका में लिए गए रुख के विपरीत है।विद्वान वकील यह भी प्रस्तुत करते हैं कि आरोप-पत्र 05.02.2018 पर दायर किया गया था, जो 08.11.2017 पर किशोर न्यायाधीश बोर्ड के समक्ष पहली प्रस्तुति की तारीख से 90 दिनों के भीतर था।अपीलकर्ता का मामला उस श्रेणी में आता है जहाँ चालान प्रस्तुत करने की अवधि 90 दिन है।विद्वान वकील यह भी प्रस्तुत करते हैं कि सजा की मात्रा पर निर्णय न्यायालय द्वारा मुकदमे के समापन के बाद ही लिया जाना है।यह व्याख्या नहीं की जा सकती है कि न्यायालय 10 वर्ष की अवधि से अधिक की सजा नहीं दे सकता है।किशोर न्यायाधीश अधिनियम की खंड 21 में एकमात्र शर्त यह है कि दोषी को रिहा नहीं करने की संभावना के साथ मृत्युदंड या आजीवन कारावास नहीं दिया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि दोषी को आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है, लेकिन उसे 10 साल से अधिक की सजा दी जा सकती है।सी. बी. आई. के विद्वान स्थायी वकील ने भी रतन लाल रजक बनाम राज्य सरकार में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है।

छत्तीसगढ़ (3) और चगंती सत्यनारायण और अन्य बनाम राज्य (ए. पी.)

उनके तर्कों के समर्थन में।

1. 2017(3) आर. सी. आर. (crl.) 996
2 2001(2) आर. सी. आर. (crl.) 754
3 2014 (40) आर. सी. आर. (crl.) 779
4 1987 (1) आर. सी. आर. (crl.) 40

(4) पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और विवादित आदेश के साथ-साथ फाइल पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का भी अध्ययन किया है।

(5) वर्तमान अपील में पाँच मुद्दे शामिल हैं, जिन पर विचार किया जाना आवश्यक हैः

(क) कानून के साथ टकराव में एक बच्चे द्वारा की गई हत्या के मामले में जांच को समाप्त करने के लिए क्या जांच एजेंसी के लिए उपलब्ध समय-अवधि 60 दिन या 90 दिन होगी- ऐसा न करने पर, आरोपी Cr.P.C की खंड 167 (2) के तहत वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत देने का हकदार होगा।

(ख) क्या Cr.P.C की खंड 167 (2) के प्रयोजन के लिए, चालान की प्रस्तुति अदालत के समक्ष होना आवश्यक है या क्या इसे केवल अदालत के किसी अधिकारी, जैसे कि अहलमाद के समक्ष दाखिल करना, Cr.P.C की खंड 167 (2) के अनुपालन को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त होगा।

(ग) क्या वर्तमान मामले में, चालान जांच एजेंसी द्वारा 05.02.2018 पर दायर किया गया था जैसा कि जांच एजेंसी द्वारा दावा किया गया है या 06.02.2018 पर जैसा कि वर्तमान अपीलार्थी द्वारा आरोप लगाया गया है?

(घ) यदि जाँच एजेंसी द्वारा चालान उसी दिन दायर किया जाता है जिस दिन अभियुक्त द्वारा Cr.P.C की खंड 167 (2) के तहत आवेदन दायर किया जाता है, तो क्या जमानत पर रिहा होने का अक्षम्य अधिकार, जो वैधानिक समय-अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं होने के कारण किसी अभियुक्त को प्राप्त होता है, समाप्त हो जाएगा?

(ङ) क्या वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में,Cr.P.C की खंड 167 (2) के तहत कोई अधिकार वर्तमान अपीलकर्ता को अर्जित हुआ था ताकि वह वैधानिक/चूक जमानत की राहत का हकदार हो?

(6) जहाँ तक पहले मुद्दे पर विचार किया जाता है, यह इस बात से संबंधित है कि क्या जांच एजेंसी को 60 दिनों या 90 दिनों की अवधि के भीतर चालान दायर करने की आवश्यकता है, ऐसे मामले में जिसमें कानून के साथ टकराव/conflict in law में बच्चे द्वारा कथित रूप से हत्या की गई है।अपीलकर्ता विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि चालान प्रस्तुत करने की समय अवधि 60 दिनों की होगी क्योंकि उसका मामला Cr.P.C की खंड 167 (2) (a) (ii) के दायरे में आता है।अपीलकर्ता विद्वान वरिष्ठ

अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि जाँच एजेंसी को 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरा चालान दाखिल करने की आवश्यकता है।आम तौर पर, हत्या के मामले में निर्धारित सजा या तो 'मौत' या 'आजीवन कारावास' होती है।ऐसी स्थिति में, निश्चित रूप से, जांच एजेंसी के पास जांच को समाप्त करने के लिए 90 दिनों की समय अवधि होती है-जिसमें विफल रहने पर, आरोपी खंड 167 (2) के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत लेने के अपने अधिकार का दावा कर सकता है। हालाँकि, यदि कानून के साथ टकराव में कोई बच्चा हत्या के अपराध के लिए मुकदमे का सामना कर रहा है, तो उसे न तो मौत की सजा दी जा सकती है और न ही किशोर न्यायाधीश अधिनियम की खंड 21 के प्रावधानों को देखते हुए रिहाई की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। किशोर न्यायाधीश अधिनियम की खंड 21 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"21. कानून के साथ टकराव/conflict in law में किसी भी बच्चे को इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत या भारतीय दंड संहिता या उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत, ऐसे किसी भी अपराध के लिए रिहाई की संभावना के बिना मौत या आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जाएगी।"

(7) किशोर की खंड 21 के उक्त प्रावधानों के अनुसार

न्यायाधीश अधिनियम, कानून के साथ टकराव/**conflict in law** में एक बच्चे को न तो मौत की सजा दी जा सकती है और न ही रिहाई की संभावना के बिना आजीवन कारावास के अधीन किया जा सकता है।बच्चे का मामला, जो कानून के साथ टकराव में है और हत्या के अपराध के लिए जांच या मुकदमे का सामना कर रहा है, एक ही अपराध के लिए जांच या मुकदमे का सामना करने वाले वयस्क आरोपी की तुलना में अलग आधार पर है।चूँकि कानून के साथ टकराव वाले बच्चे पर कोई न्यूनतम सजा नहीं दी जानी चाहिए, इसलिए कानून के साथ टकराव में उक्त बच्चे का मामला खंड **167 (2) (ए) (ii) Cr.P.C** के दायरे में आएगा। तदनुसार, जांच को समाप्त करने के लिए **60** दिनों की अवधि है न कि **90** दिनों की।खंड **167 Cr.P.C.** के प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"167. प्रक्रिया जब जांच चौबीस घंटे में पूरी नहीं की जा सकती है -

(2) जिस मजिस्ट्रेट को इस खंड के तहत कोई अभियुक्त व्यक्ति भेजा जाता है, वह समय-समय पर अभियुक्त को ऐसी हिरासत में रखने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, जो ऐसा मजिस्ट्रेट ठीक समझे, और यदि उसके पास मामले की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसे मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध करें, और आगे की नजरबंदी को अनावश्यक समझते हुए, वह अभियुक्त को ऐसी अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजने का आदेश दे सकता हैः

बशर्ते कि -

(क) मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को पुलिस की अभिरक्षा के अलावा पंद्रह दिनों की अवधि के बाद हिरासत में रखने के लिए अधिकृत कर सकता है; यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं, लेकिन कोई भी मजिस्ट्रेट इस अनुच्छेद के तहत अभिरक्षा में अभियुक्त व्यक्ति को कुल अवधि से अधिक के लिए हिरासत में रखने के लिए अधिकृत नहीं करेगा -

(i) नब्बे दिन, जहां जांच मौत, आजीवन कारावास या दस साल से कम की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित है;

((ख) साठ दिन, जहां अन्वेषण किसी अन्य अपराध से संबंधित है, और, यथास्थिति, नब्बे दिन या साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर, अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाएगा यदि वह जमानत देने के लिए तैयार है और जमानत देता है, और इस उप-खंड के तहत जमानत पर रिहा किया गया प्रत्येक व्यक्ति उस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अध्याय XXXIII के प्रावधानों के तहत इस तरह से रिहा किया गया समझा जाएगा।

(8) संहिता की खंड 167 (2) के अवलोकन पर, जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, यह स्पष्ट है कि जांच एजेंसी को उस मामले में जांच समाप्त करने के लिए दी गई समय अवधि जहां मामला मौत की सजा, आजीवन कारावास या 10 साल से कम की अवधि के लिए कारावास से संबंधित है, वह 90 दिनों की होगी; जबकि किसी अन्य मामले में जांच एजेंसी को दी गई समय अवधि 60 दिनों की होगी-जिसमें विफल रहने पर, आरोपी को वैधानिक/default/चूक जमानत लेने का एक अक्षम्य अधिकार प्राप्त होता है।अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि मामले में जाँच एक ऐसे अपराध से संबंधित है, जो मौत से दंडनीय नहीं है और कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं है-वर्तमान अपीलकर्ता 60 दिनों की अवधि के भीतर जाँच समाप्त नहीं होने की स्थिति में

वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा होने का हकदार बन गया है।यह भी तर्क दिया गया है कि यह दावा करना जांच एजेंसी का काम है कि उसके पास चालान पेश करने के लिए 90 दिनों की अवधि थी, उसे यह दिखाना होगा कि न्यूनतम सजा, जो दी जानी चाहिए वह या तो मौत है या आजीवन कारावास या 10 साल से कम की अवधि के लिए कारावास है। जाँच एजेंसी के मामले के अनुसार, मुक़दमे के समापन के बाद निचली अदालत या तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास कर सकती है। जांच एजेंसी के पास जांच समाप्त करने के लिए 90 दिन हैं न कि 60 दिन।यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि दोनों पक्षों ने राकेश कुमार पॉल बनाम असम राज्य 5 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है।हालाँकि, उक्त निर्णय का अनुच्छेद Nos.25 और 27 प्रासंगिक हैं, जिन्हें निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

“हालांकि यह सच है कि केवल इसलिए कि अधिनियम में न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि केवल न्यूनतम सजा अधिरोपणीय है।समान रूप से, यह सुझाव देने के लिए भी कुछ नहीं है कि केवल अधिकतम वाक्य अधिरोपणीय है।या तो सजा दी जा सकती है और यहाँ तक कि बीच में कुछ भी।संतुलन कहाँ स्थापित किया जा सकता है?यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह अंततः अदालत को तय करना है कि उपलब्ध सीमा को देखते हुए कौन सी सजा दी जानी चाहिए।निस्संदेह, विधानमंडल न्यूनतम सजा (कम से कम नहीं) निर्धारित करके सजा सुनाने वाली अदालत को बाध्य कर सकता है और यह अधिकतम सजा भी निर्धारित कर सकता है।यदि न्यूनतम निर्धारित किया जाता है, तो सजा सुनाने वाले न्यायाधीश के पास उस सजा के लिए "कम से कम" सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है।इसलिए, (और अन्य प्रावधानों में) Cr.P.C. की खंड 167 (2) के परन्तुक (ए) के खंड में आने वाले "कम से कम" शब्दों को उनका स्वाभाविक और स्पष्ट अर्थ दिया जाना चाहिए, जो न्यूनतम सीमा से कम नहीं है और Cr.P.C. की खंड 167 के मामले में. ये शब्द न्यूनतम 10 साल के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित होने चाहिए।

27. यह सच है कि मौत की सजा या आजीवन कारावास या 10 साल तक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध एक गंभीर अपराध है जिसमें गहन और शायद व्यापक जांच शामिल है।अतः ऐसा प्रतीत होता है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए ऐसे मामलों में जांच अधिकारी को 90 दिनों की विस्तारित अवधि उपलब्ध होनी चाहिए।दूसरे शब्दों में, जाँच की अवधि अपराध की गंभीरता से संबंधित होनी चाहिए-समझ में आता है।इसकी

तुलना उस अपराध से की जा सकती है जिसमें भा.दं.सं. सी/IPC या किसी अन्य दंडात्मक अधिनियम के तहत अधिकतम सजा (मान लीजिए) 7 साल, अपराध है।

(5) 2017 (3) आर. सी. आर. (सी. आर. एल/Crl.) 996)

90 दिनों की जांच की विस्तारित अवधि के लिए पर्याप्त गंभीर या गंभीर नहीं होना। यह निश्चित रूप से एक संभावित दृष्टिकोण है और वास्तव में Cr.P.C. अपराध की गंभीरता के आधार पर 'डिफ़ॉल्ट जमानत' के उद्देश्यों के लिए जांच की अवधि में अंतर करता है। फिर भी, व्याख्या में किसी भी अनिश्चितता या अस्पष्टता से बचने के लिए, कानून को दो खंडों के साथ लागू किया गया था। दस साल से कम के कारावास से दंडनीय अपराधों को एक डिब्बे में रखा गया है जो उन्हें मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों के बराबर करता है। अपराधों की इस श्रेणी में निस्संदेह गहन जांच की आवश्यकता होती है क्योंकि न्यूनतम सजा काफी कठोर होती है। अन्य सभी अपराधों को एक अलग डिब्बे में रखा गया है, क्योंकि वे कम न्यूनतम सजा का प्रावधान करते हैं, भले ही अधिकतम सजा दस साल से अधिक हो सकती है। हालांकि ऐसे अपराधों की गहन जांच की भी आवश्यकता हो सकती है (क्योंकि अधिकतम काफी अधिक है) उन्हें एक अलग डिब्बे में रखा गया है क्योंकि सजा सुनाने वाली अदालत द्वारा कम न्यूनतम अधिरोपणीय है, और इस तरह जांच के दौरान कारावास की अवधि को कम किया गया है जिसे शीघ्रता से समाप्त किया जाना चाहिए। कट-ऑफ, चाहे किसी को पसंद हो या न हो, विधानमंडल के विवेक पर आधारित है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए।"

(9) अपीलकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उक्त पैराग्राफ पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया कि विधानमंडल ने खंड 167 (2) Cr.P.C को दो अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया है। यह तर्क दिया गया है कि जांच एजेंसी के पास ऐसे मामले में जांच को समाप्त करने के लिए 90 दिनों की अवधि होगी जहां न्यूनतम सजा या तो मौत, आजीवन कारावास या 10 साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा है। यह भी तर्क दिया गया है कि केवल उन मामलों में जहां न्यूनतम सजा 10 साल से अधिक की कैद या आजीवन कारावास या मौत की है, जांच एजेंसी को जांच समाप्त करने के लिए 90 दिनों की अवधि दी जाती है। अर्थात्, यदि वर्तमान की तरह न तो मृत्युदंड की सजा है और न ही आजीवन कारावास की सजा है, तो यदि 60 दिनों की अवधि के भीतर चालान प्रस्तुत/दायर नहीं किया जाता है, तो अभियुक्त डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा होने का हकदार होगा।

(10) वर्तमान मामले में, माननीय के निर्णय का अवलोकन

राकेश कुमार पॉल के मामले (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय यह खुलासा करेगा कि उक्त निर्णय तीन-न्यायाधीशों की पीठ/bench द्वारा दिया गया था, जिसमें प्रत्येक माननीय न्यायाधीश द्वारा अलग-अलग निर्णय दिए गए है. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर के फैसले पर भरोसा रखा है, जबकि सी. बी. आई. के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी. पंत और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए कहा है कि वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा व्यक्त किए गए इस तरह के तर्क को अन्य दो न्यायाधीशों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और इसलिए, बहुमत के निर्णय के अनुसार, जांच एजेंसी को उपलब्ध समय अवधि, एक ऐसे मामले में जहां अधिकतम आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है, भले ही कोई न्यूनतम सजा निर्धारित न हो-90 दिनों की होगी।इस संबंध में, न्यायाधीश प्रफुल्ल सी. पंत द्वारा दिए गए निर्णय के पैराग्राफ No.71 पर निर्भरता रखी गई है, जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

“71. उपरोक्त सादृश्य से, मेरी राय है कि विधायिका का इरादा यह था कि यदि कोई अपराध दस साल तक के कारावास से दंडनीय था, तो यह संहिता की खंड 167 (2) (ए) (आई) के प्रावधान के भीतर आता है, और जांच के लिए अनुमेय अवधि नब्बे दिन है।जांच के लिए अनुमेय समय अवधि को साठ दिनों से बढ़ाकर नब्बे दिन करने का विधानमंडल का इरादा उन अपराधों को शामिल करना है जिनमें कम से कम दस साल या उससे अधिक की सजा दी जा सकती है।इसलिए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, हालांकि संहिता की खंड 167 (2) (ए) (आई) में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "दस साल से कम नहीं" ने कुछ अस्पष्टता पैदा की है, लेकिन विधायिका के वास्तविक इरादे में ऐसे सभी अपराध शामिल प्रतीत होते हैं जिनमें दस साल तक का कारावास एक अधिनिर्णय योग्य सजा है।दूसरे शब्दों में, उन अपराधों के लिए जिनकी सजा दस साल के कारावास तक हो सकती है, आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए अनुमेय अवधि नब्बे दिन होगी, और नब्बे दिनों की अवधि के बाद ही, आरोपी आरोप-पत्र दाखिल न करने के लिए चूक पर जमानत का हकदार होगा।(वर्तमान मामले में, नब्बे दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर किया जाता है)।मैं यह भी जोड़ सकता हूं कि चूंकि "दस साल से कम नहीं" अभिव्यक्ति ने व्याख्या में अस्पष्टता पैदा की है, इसलिए विधायिका के लिए सबसे अच्छा तरीका उचित शब्दों का उपयोग करके अपने इरादे को स्पष्ट करना होगा।”

(11) उपर्युक्त पैराग्राफ के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि यह स्पष्ट रूप से

अभिनिर्धारित किया गया है कि जांच को पूरा करने के लिए अनुमेय समय अवधि को 60 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन करने का विधानमंडल का इरादा उन अपराधों को शामिल करना है जिनके लिए सजा कम से कम 10 वर्ष या उससे अधिक है-लेकिन यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी ऐसे अपराध के मामले में जिसके लिए सजा दस वर्ष तक बढ़ सकती है, चालान दाखिल करने के लिए अनुमेय अवधि 90 दिन होगी।यह स्पष्ट है कि ऐसे मामले में जहां न्यायालय दस साल से अधिक के कारावास का आदेश दे सकता है, जांच एजेंसी के लिए उपलब्ध समय अवधि 90 दिनों की होगी।इसी तरह, सी. बी. आई. के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायाधीश दीपक गुप्ता द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा रखा गया है, जिन्होंने खंड 167 (2) Cr.P.C की व्याख्या करते हुए कहा हैः-

“89. हम केवल खंड 167 (2) (ए) (आई) में आने वाले दस साल से कम की अवधि के लिए वाक्यांश की व्याख्या से संबंधित हैं, जिसमें 90 दिनों की अवधि का प्रावधान है जहां जांच मौत, आजीवन कारावास या 10 साल से कम की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित है।

90. मेरे विचार में, किसी भी शब्दार्थिक जिम्नास्टिक में शामिल हुए बिना, इस प्रावधान का अर्थ आत्यन्तिक रूप स्पष्ट है।इसमें तीन प्रकार के अपराधों की परिकल्पना की गई हैः

(क) ऐसे अपराध जो मृत्युदंड के योग्य हों;

(ख) ऐसे अपराध जिनके लिए आजीवन कारावास की सजा हो।

(ग) ऐसे अपराध जो 10 वर्ष से कम की अवधि के साथ दंडनीय हैं।

91. मेरे विचार में अधिनियम की भाषा स्पष्ट और स्पष्ट है।अपराधों की तीन श्रेणियों में से, हमें केवल उस श्रेणी के अपराधों से निपटने की आवश्यकता है जहां निर्धारित सजा 10 साल से कम नहीं है।यदि कोई अपराध मौत की सजा के योग्य है तो न्यूनतम सजा जो भी हो, जांच की अवधि 90 दिनों की होगी।इसी तरह, यदि अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय है, भले ही न्यूनतम सजा 10 साल से कम हो, तो 'डिफ़ॉल्ट जमानत' से पहले हिरासत की अवधि 90 दिन होगी।

92. खंड 167 के विधायी इतिहास को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि विधायिका अधिक गंभीर अपराधों का पता लगा रही थी और आरोपी को 'डिफ़ॉल्ट जमानत' देने का हकदार बनने से पहले जांच एजेंसी को जांच पूरी करने के लिए और 30 दिन का समय दे

रही थी।

इन अपराधों को तीन वर्गों में वर्गीकृत करता हैः

I. पहली श्रेणी में वे अपराध शामिल हैं जहाँ अधिकतम सजा मौत थी।

II. दूसरी श्रेणी में वे अपराध शामिल हैं जहाँ अधिकतम सजा आजीवन कारावास है।

III. तीसरी श्रेणी में वे अपराध शामिल हैं जो 10 साल से कम की अवधि के साथ दंडनीय हैं।"

(12) न्यायाधीश दीपक गुप्ता द्वारा दिए गए फैसले से यह स्पष्ट है जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि अपराध मौत की सजा के योग्य है-तो न्यूनतम सजा जो भी हो, जांच की अवधि 90 दिनों की होगी।इसी तरह, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय है, लेकिन न्यूनतम सजा 10 वर्ष से कम है, तो वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत से पहले निरोध की अवधि 90 दिन होगी।इस प्रकार, एक ऐसे मामले में जिसमें आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है, भले ही कोई न्यूनतम सजा निर्धारित न हो-जांच एजेंसी को जांच समाप्त करने के लिए 90 दिनों की अवधि उपलब्ध होगी।

(13) वर्तमान मामले में, किशोर न्यायाधीश अधिनियम की खंड 21 के नंगे अवलोकन से पता चलता है कि 'मौत' और 'रिहाई की संभावना के बिना आजीवन कारावास' के अलावा कोई भी सजा कानून के साथ संघर्ष में एक बच्चे पर लगाई जा सकती है।यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि समय बीतने के साथ, हमारे न्यायालयों द्वारा दो प्रकार के आजीवन कारावास को मान्यता दी गई है, जो किसी अभियुक्त को दी जा सकती है।इस संबंध में, भारत संघ बनाम वी. श्रीहरण (6) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भा.दं.सं. सी. की खंड 45 के साथ पठित खंड 53 के संदर्भ में आजीवन कारावास का अर्थ है दोषी का शेष जीवन कारावास।हालाँकि, यह भी माना गया है कि एक दोषी, जिसे आजीवन कारावास की सजा दी गई है, उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 और 61 के तहत प्रदान की गई छूट आदि का दावा करने का अधिकार होगा, जैसा कि मामला हो।इसके अलावा, माननीय संविधान पीठ ने इस विचार की पुष्टि की कि अदालतें, कुछ मामलों में, सजा की एक विशेष श्रेणी बना सकती हैं-जहां वे 'मौत' के बजाय, आजीवन कारावास की

सजा दे सकते हैं-लेकिन, इसे 'माफी' के प्रावधानों के आवेदन से परे रख सकते हैं।

(6) 2016(1) आर. सी. आर. (क्रोरल/Crl.) 234

इस प्रकार, कुछ मामलों में, अदालतों के लिए यह खुला है कि वे किसी दोषी को आजीवन कारावास की सजा दे सकते हैं, लेकिन माफी आदि मांगने के उसके अधिकार को छीन सकते हैं, और इस तरह रिहाई की किसी भी संभावना को खारिज कर सकते हैं।यह रिहाई की संभावना के बिना 'आजीवन कारावास' की एक ऐसी श्रेणी है जिसे किशोर न्यायाधीश अधिनियम की खंड 21 के आधार पर कानून के साथ संघर्ष में एक बच्चे के मामले में बाहर रखा गया है। हालांकि, कानून के साथ टकराव में एक बच्चे को हमेशा आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है।ऐसी परिस्थितियों में, जब अधिकतम सजा, जो कानून के साथ टकराव में एक बच्चे पर लगाई जा सकती है, आजीवन कारावास है-तो जांच एजेंसी को जांच समाप्त करने के लिए उपलब्ध समय अवधि 90 दिनों की होगी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस मुद्दे पर बहुमत का दृष्टिकोण, इस हद तक निर्णायक होंगे कि जिसे न्यायाधीश प्रफुल्ल सी. पंत और न्यायाधीश दीपक गुप्ताद्वारा दिए गए फैसले से निकाला जा सकता है।जब अधिकतम सजा जो लगाई जा सकती है वह आजीवन कारावास है-तब, इस तथ्य के बावजूद कि कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं है-खंड 167 (2) Cr.P.C के प्रयोजनों के लिए जांच एजेंसी को उपलब्ध समय अवधि 90 दिनों की होगी।

(14) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि (क) के रूप में जारी किए जाने वाले पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि जांच एजेंसी को जांच पूरी करने के लिए उपलब्ध समय अवधि, कानून के साथ संघर्ष में एक बच्चे से जुड़े मामले में, जिस पर हत्या का अपराध करने का आरोप है, वह 90 दिनों की होगी न कि 60 दिनों की।

(15) अंतिम सुनवाई के दौरान, कई तर्क दिए गए कि वर्तमान मामले में चालान वास्तव में कब दायर किया गया था।जाँच एजेंसी द्वारा यह आग्रह किया गया था कि उसने अदालत के अहलमाद के समक्ष चालान पेश करके 05.02.2018 पर ही चालान प्रस्तुत किया था। इसके विपरीत, यह आग्रह किया गया था कि Cr.P.C की खंड 167 (2) की आवश्यकता अदालत के समक्ष चालान प्रस्तुत करना है; और यह कि इसे अहलमाद जैसे न्यायालय के किसी भी पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना खंड 167 (2) Cr.P.C का अनुपालन नहीं होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त विवाद अब एकीकृत नहीं है और इस न्यायालय द्वारा(गुरचरण सिंह @मिंटू बनाम हरियाणा राज्य) 7 में पहले ही जवाब दिया जा चुका है और

उक्त निर्णय के प्रासंगिक हिस्से को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

“7.पहला सवाल जिस पर इस न्यायालय के समक्ष विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या पहले चालान प्रस्तुत किया गया था।

(7) 2016(1) लॉ हेराल्ड 679

न्यायालय का अहमद कानूनी प्रस्तुति है या नहीं?खंड 173 (2) Cr.P.C. निम्नानुसार प्रदान करती हैः-

173. जाँच पूरा होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट-(1) 66।

(2) (i) जैसे ही यह पूरा हो जाता है, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी गोपाल कृष्ण 2016/02:11 15:11 को भेजेगाःमैं इस दस्तावेज़ की सटीकता और प्रामाणिकता की पुष्टि करता हूं उच्च न्यायालय चंडीगढ़ मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार दिया गया है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक रिपोर्ट में कहा गया है -

(क) पक्षकारों के नाम;

((ख) सूचना की प्रकृति;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम जो मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते हैं;

((घ) क्या ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अपराध किया गया है और यदि है, तो किसके द्वारा किया गया है;

(ई) क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है;

(च) क्या उसे उसके मुचलके पर रिहा किया गया है और, यदि हां, तो प्रतिभू के साथ या उसके बिना;

(छ) क्या उसे खंड 170 के तहत हिरासत में भेज दिया गया है।

(i) अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, सूचित करेगा, जिसे अपराध करने से संबंधित जानकारी पहली बार दी गई थी।

8. यह स्पष्ट है कि चालान मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है न कि अहलमद के समक्ष।चालान शाम 4:45 बजे यानी अदालत के निर्धारित समय/घंटों के बाद पेश किया गया।यदि मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं होता तो चालान इलाका मजिस्ट्रेट के आवास पर या ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता था।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह विवादित नहीं है कि 11.11.2015 और 12.11.2015 छुट्टी थी क्योंकि दूसरा शनिवार और रविवार था।मजिस्ट्रेट के आदेश से पता चलता है कि खंड 167 (2) Cr.P.C के तहत आवेदन कब दाख़िल स्थानांतरित किया गया था और केवल तभी जब मजिस्ट्रेट ने अहलमद से रिपोर्ट माँगी गई, अहलमद ने अदालत के ध्यान में लाया कि उसके सामने शाम 4:45 बजे 10.11.2015 पर चालान पेश किया गया था।मूल फाइल की भी मांग की गई है, जिसमें भी यही तथ्य है।वास्तव में, अहलमद ने शाम 4:45 बजे 10.11.2015 पर चालान की प्राप्ति के संबंध में जांच अधिकारी को रसीद दी।

11. इसलिए, यदि चालान के कागजात अहलमाद के पास छोड़ दिए जाते हैं, तो यह मजिस्ट्रेट के समक्ष खंड 173 (2) Cr.P.C के तहत अंतिम रिपोर्ट की उचित प्रस्तुति नहीं है।इसलिए, चालान प्रस्तुत करने की तारीख को 13.11.2015 के रूप में लिया जाना चाहिए।

23. ऐसा होने पर, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि 90 दिनों की अवधि की गणना करने के उद्देश्य से, 15.8.2015, जब उसे पहली बार मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था और हिरासत में भेज दिया गया था, को शामिल किया जाना है।यदि इसे इस प्रकार शामिल किया जाता है, तो 90 दिनों की अवधि 12.11.2015 पर समाप्त हो जाएगी।चूंकि, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अहलमाद के समक्ष कागजात दाखिल करना खंड 173 (2) Cr.P.C के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष चालान प्रस्तुत करना नहीं है, इसलिए, चालान को 13.11.2015 पर प्रस्तुत किया गया माना जाता है जब 90 दिनों की अवधि पहले ही बीत चुकी थी।

(16) उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा यह कहते हुए विवाद का निपटारा किया गया था कि यदि चालान को अहलमाद के पास छोड़ दिया जाता है-तो इसे अंतिम रिपोर्ट की उचित प्रस्तुति के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, जैसा कि खंड 173 (2) Cr.P.C के तहत परिकल्पना की गई है। यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि

अहलमद के समक्ष केवल चालान पत्र प्रस्तुत करना खंड 167 (2) Cr.P.C के

अनुपालन के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि निर्धारित अवधि के भीतर चालान दाखिल न करने से अभियुक्त को वैधानिक/चूक default जमानत पर रिहा किए जाने का अक्षम्य अधिकार मिलता है।यदि प्रतिवादी के तर्क को स्वीकार किया जाना है, कि कलम 167 (2) Cr.P.C के अनुपालन का निर्धारण करने के उद्देश्यों के लिए अहलमद के समक्ष केवल चालान प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा, तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें अहलमद या किसी अन्य अधिकारी द्वारा पूर्व-समय निर्धारण या पूर्व-समय निर्धारण में संलिप्तता या जांच एजेंसी के साथ मिलीभगत से अभियुक्त का अक्षम्य अधिकार विफल हो सकता है।इसी तरह, गंभीर अपराधों में, जांच एजेंसी के प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया जा सकता है यदि अहमद या कोई अन्य व्यक्ति आरोपी के साथ मिलीभगत करता है और गलत तारीख या समय दिखाता है जिस पर चालान प्रस्तुत किया गया था, ताकि आरोपी को वैधानिक/पूर्वनिर्धारित जमानत पर रिहा करने में सुविधा हो सके। ।ऐसी स्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता की आदेश 167 (2) की एकमात्र प्रशंसनीय व्याख्या यह होनी चाहिए कि चालान को केवल न्यायालय और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

(17) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, (ख) के रूप में जारी किए जाने वाले दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या चालान निर्धारित समय अवधि के भीतर अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है-वह तिथि जिस पर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, प्रासंगिक होगी न कि वह तिथि जिस पर उसे अहलमद के समक्ष प्रस्तुत किया गया होगा। या केवल अहलमद या किसी अन्य पदाधिकारी के पास देने से सीआरपीसी की धारा167(2) का अनुपालन पूरा नहीं होगा .

(18) वर्तमान मामले में, आज तक एक विवाद पैदा हो गया है जिस पर अदालत के समक्ष चालान दायर किया गया था।यह विवाद में नहीं है कि खंड 167 (2) Cr.P.C के तहत आवेदन वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा 05.02.2018 पर सुबह 10.00 पर दायर किया गया था, जैसा कि न्यायालय द्वारा पारित ज़िमनी आदेश से परिलक्षित होता है, जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

“वर्तमान हाजिरी:एस. एस. एस. गुलिया, राज्य के पीपी।

Sh.Vishal गुप्ता और श्री. संदीप अनेजा, अधिवक्ता, अभियुक्त के वकील।

किशोर न्यायाधीश (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की खंड 2 (33) और 21 के साथ पठित खंड 167 (2) (ए) (ii) Cr.P.C के तहत जमानत आवेदन को स्थानांतरित/दाख़िल करने के कारण ली गई फाइल।आवेदन की प्रति पी. पी./सी. बी. आई. को प्रदान की जाए और आवेदन पर विचार करने के लिए मामला सामने आए।इस बीच, कार्यालय चालान दाखिल करने के बारे में रिपोर्ट करेगा।आवेदक पूर्वाहन लिए विद्वान अधिवक्ता पूर्वाहन अनुरोध पर, यह प्रमाणित किया जाता है कि ये आवेदन 10.00 सुबह तेज पर दाख़िल/ स्थानांतरित किया जाता है।

एसडी/-

(जे. एस. कुंडू)

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम

आदेश की तिथि 05.02.2018 "

(19) अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि उसी दिन एक और आदेश पारित किया गया जिसमें अदालत ने कहा कि अहलमद ने स्पष्ट किया है कि चालान आज ही सी. बी. आई. द्वारा अर्थात् 05.02.2018 पर प्रस्तुत किया गया है। 05.02.2018 पर पारित उक्त दूसरा आदेश नीचे के रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया है

तैयार संदर्भ का उद्देश्यः- "वर्तमान हाजिरी :Sh.Vishal गुप्ता और श्री. संदीप अनेजा, अधिवक्ता, आवेदक-किशोर के वकील।

एस. सुशील टेकरीवाल, अधिवक्ता, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता(जाँच अधिकारी अजय कुमार बस्सी, डीएसपी, सीबीआई) (शिकायतकर्ता वरुण चंद्र ठाकुर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित)।आपराधिक/criminal अहलमद ने रिपोर्ट बनाकर स्पष्ट किया है कि चालान आज ही सी. बी. आई. द्वारा यानी 05.02.2018 पर जमा किया गया है।जमानत याचिका पर दलीलें सुनी गईं।सम तिथि के मेरे अलग आदेश के अनुसार, जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है।चालान की प्रति की आपूर्ति के लिए पहले से तय तिथि 12.02.2018 पर मामला सामने आएगा।

एसडी/- (जे. एस. कुंडू)

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम आदेश की तिथि 05.02.2018 "

(20) कि वर्तमान अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उक्त आदेश सही तस्वीर का संकेत नहीं देता है। अपीलकर्ता ने विभिन्न दस्तावेजों को जोड़कर ऐसा करने का आग्रह किया है और यह अंकित करने की कोशिश की है कि चालान वास्तव में 06.02.2018 पर दाखिल किया गया था। इसलिए, यह आग्रह किया गया कि चालान दाखिल करने की वास्तविक तिथि 06.02.2018 होगी न कि 05.02.2018, जैसा कि अहलमद ने अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट में कहा है और जैसा कि अदालत ने कहा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में जहां एक स्पष्ट न्यायिक आदेश है कि चालान 05.02.2018 पर ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है-इस न्यायालय के लिए यह जांच शुरू करना न तो संभव है और न ही अनुमति है कि क्या आदेश घटनाओं के क्रम को सही ढंग से दर्ज करता है या नहीं। यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय को यह मान लेना है कि विचाराधीन न्यायिक आदेश ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की खंड 114, चित्रण (ई) के तहत परिकल्पित कानून की धारणा को ध्यान में रखते हुए घटनाओं के अनुक्रम को सही ढंग से दर्ज किया है। साक्ष्य अधिनियम की खंड 114 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"114. न्यायालय कुछ तथ्यों के अस्तित्व का अनुमान लगा सकता है।—न्यायालय विशेष मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण और सार्वजनिक और निजी व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए किसी भी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगा सकता है, जिसके होने की संभावना है।

XXX XXX XXX

(ङ) न्यायिक और आधिकारिक कार्य नियमित रूप से किए जाते रहे हैं।

XXX XXX "

(21) साक्ष्य अधिनियम की खंड 114, चित्रण (ई) के एक अवलोकन से पता चलता है कि कानून में एक धारणा है कि न्यायिक कार्य नियमित रूप से किए जाते हैं। इस प्रकार, केवल अपीलकर्ता के पूछने पर या किसी दस्तावेज को जोड़कर, यह आग्रह नहीं किया जा सकता है कि चालान वास्तव में 06.02.2018 पर प्रस्तुत किया गया था और अहलमद द्वारा गलत रिपोर्ट दी गई है और आदेश में चालान प्रस्तुत करने की तारीख और समय भी गलत तरीके से दर्ज किया गया है, क्योंकि यह धारणा है कि अहलमाद द्वारा किया गया आधिकारिक कार्य तथ्यात्मक रूप से सही है और इसी तरह, विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित न्यायिक आदेश

जो दर्ज करता है कि चालान वास्तव में 05.02.2018 पर प्रस्तुत किया गया था, वह भी सही है।

(22) वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के आधार पर भी, अपीलकर्ता द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि चालान 05.02.2018 पर दोपहर 3 बजे दाखिल किया गया था। अपील के आधार पर किए गए प्रासंगिक कथन को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"11. उसी दिन. बाल अदालत/ए. एस. जे. गुरुग्राम ने डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन पर नोटिस जारी किया और उसी दिन के लिए चालान दाखिल करने के लिए रिपोर्ट मांगी, जो आदेश संलग्नक पी-से सबूत है।इसके बाद, चालान 05.02.2018 पर 03.00 बजे दायर किया गया और दलीलें सुनने के बाद, डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया।एल. डी. न्यायाधीश ने आवेदन यू/एस/under section 167 (2) Cr.P.C. को अस्वीकार करते हुए इस बात पर विचार नहीं किया कि भारतीय दंड संहिता के तहत सजा के बारे में प्रश्न जिसे लागू नहीं किया जा सकता है, उस पर 60/90 दिनों की अवधि के निर्धारण के उद्देश्य से विचार किया जाएगा।"

(23) अन्यथा भी, यह मामला एक ठोस सार्वजनिक नीति का भी है कि एक न्यायिक आदेश पर विवाद नहीं किया जा सकता है, जैसा कि महाराष्ट्र राज्य बनाम रामदास श्रीनिवास नायक और अन्य 8 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, जिसमें इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः-

(8) 1982 आकाशवाणी (अनुसूचित जाति) 1249 136

"4.....हमें डर है कि हम जांच शुरू नहीं कर सकते की उच्च न्यायालय में क्या हुआ।यह बस नहीं किया जाता है।सार्वजनिक नीति हमें रोकती है न्यायिक शिष्टाचार हमें रोकता है। न्यायिक अभिलेख के मामले निर्विवाद हैं।वे संदेह के लिए खुले नहीं हैं।न्यायाधीशों को अखाड़े में नहीं घसीटा जा सकता है।"मुकदमों के खेल में निर्णयों को केवल काउंटर के रूप में नहीं माना जा सकता है।(सोमसुंदरन बनाम सुब्रमण्यन में लॉर्ड एटकिंसन के अनुसार, ए. आई. आर. 1926 पी. सी. 136)।हम न्यायाधीशों के अपने फैसले में दर्ज बयान को प्रतिग्रहण करने के लिए बाध्य हैं, कि अदालत में क्या हुआ।हम न्यायाधीशों के बयान का बार में दिए गए बयानों या शपथ पत्र और अन्य साक्ष्यों द्वारा खंडन करने की अनुमति नहीं दे

सकते।यदि न्यायाधीश अपने निर्णय में कहते हैं कि उनके समक्ष कुछ किया गया था, कहा गया था या स्वीकार किया गया था, तो वह विषय पर अंतिम शब्द होना चाहिए।सिद्धांत अच्छी तरह से तय किया गया है कि अदालत के फैसले में दर्ज सुनवाई में जो हुआ, उसके बारे में तथ्य के बयान इस तरह से बताए गए तथ्यों के निर्णायक हैं और कोई भी शपथ पत्र या अन्य साक्ष्य द्वारा ऐसे बयानों का खंडन नहीं कर सकता है।"

(24) साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुमान के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून को ध्यान में रखते हुए-यह अभिनिर्धारित करना होगा कि जिस आदेश के तहत यह दर्ज किया गया है कि चालान 05.02.2018 पर प्रस्तुत किया गया है, वह घटनाओं के अनुक्रम को सही ढंग से दर्ज करता है।

(25) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त (ग) के रूप में तैयार किए गए तीसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि, वर्तमान मामले में खंड 167 (2) Cr.P.C की प्रयोज्यता निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए-चालान को 05.02.2018 पर प्रस्तुत किया गया समझा जाना चाहिए।

(26) वर्तमान मामले में, अभिलेख के केवल अवलोकन से पता चलता है कि खंड 167 (2) Cr.P.C के तहत आवेदन को 05.02.2018 पर 10.00 पर स्थानांतरित/दाख़िल किया गया था।यह विवाद में नहीं है कि इसके बाद ही सी. बी. आई. द्वारा चालान पेश किया गया था। जाँच एजेंसी की ओर से यह आग्रह किया गया है कि यदि आवेदन दायर किया जाता है और उसी दिन चालान भी दायर किया जाता है-तो अपीलकर्ता का वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा होने का अधिकार अपने आप समाप्त हो जाएगा।इस तर्क को निचली अदालत ने वर्तमान मामले में भी स्वीकार किया है, जिसमें उसने रतन लाल रजाक बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 9 के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आवेदन और चालान उसी दिन एक साथ दायर किया जाता है-वैधानिक/चूक जमानत का लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उक्त निर्णय के नंगे अवलोकन से पता चलता है कि उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुँचते समय, न्यायालय ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य 10 के निर्णय पर व्यापक रूप से भरोसा किया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि खंड 167 (2) Cr.P.C के तहत आवेदन विचाराधीनता रहने के दौरान, चालान जांच एजेंसी द्वारा दायर किया जाता है, तो यह अभियुक्त कोवैधानिक/चूक जमानत कीराहत के लिए अयोग्य

(9) 2014 (40) आर. सी. आर. (सी. आर. एल/Crl.) 779

घोषित कर देगा।वर्तमान मामले में, विवाद का जवाब देने के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की एक श्रृंखला शुरू करना अनिवार्य होगा, जिनका इस न्यायालय द्वारा विचार किए जा रहे प्रश्न पर सीधा असर पड़ता है।पहला निर्णय, जिसका उपरोक्त प्रश्न पर सीधा असर है, उदय मोहनलाल आचार्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 11 के मामले में दिया गया होगा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि 90 दिनों या 60 दिनों की अवधि की समाप्ति पर, जैसा भी मामला हो, अभियुक्त को वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा होने के लिए एक अक्षम्य अधिकार प्राप्त होता है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियुक्त द्वारा अपने अक्षम्य अधिकार को लागू करने के लिए दायर खंड 167 (2) Cr.P.C के तहत आवेदन-जांच एजेंसी द्वारा चालान की बाद की प्रस्तुति से निराश नहीं किया जा सकता है।उक्त निर्णय के प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

“12. ..... व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के पोषित उद्देश्यों में से एक है और इसे वंचित करना केवल कानून के अनुसार और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप ही हो सकता है।जब कानून यह प्रावधान करता है कि मजिस्ट्रेट खंड 167 की उप-खंड (2) के परंतुक में दर्शाई गई अधिकतम अवधि तक आरोपी को हिरासत में रखने के लिए अधिकृत कर सकता है, तो जांच एजेंसी द्वारा चालान दायर किए बिना अवधि से आगे कोई भी हिरासत एक छल होगा और कानून के अनुसार और दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगा, और इस तरह, संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो सकता है।दण्ड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद किसी आरोपी को हिरासत में रखने को अधिकृत करता हो।

(10) 2010 (1) आर. सी. आर. (सी. आर. एल./Crl.) 303

(11) 2001(2) आर. सी. आर. (क्रोरल/Criminal) 452

खंड 167 की उप-खंड (2) के परंतुक में, स्पष्टीकरण I में इंगित आकस्मिकता को छोड़कर, अर्थात् यदि अभियुक्त जमानत नहीं देता है।इस अर्थ में यह कहा जा सकता है कि यदि अवधि समाप्त होने के बाद, जमानत पर रिहा होने के लिए एक आवेदन दायर किया जाता है, और आरोपी जमानत देने की पेशकश करता है, और इस तरह अपने अक्षम्य

अधिकार का लाभ उठाता है और फिर जमानत का आदेश कुछ नियमों और शर्तों पर पारित किया जाता है, लेकिन आरोपी जमानत देने में विफल रहता है, और उस समय चालान दायर किया जाता है, तो संभवतः यह कहा जा सकता है कि आरोपी का अधिकार समाप्त हो गया था।लेकिन जब तक अभियुक्त एक आवेदन दायर करता है और न्यायालय के उचित आदेशों द्वारा रिहा होने पर जमानत की पेशकश करने के लिए आवेदन में संकेत देता है, तब तक मजिस्ट्रेट के उपलब्ध नहीं होने और मामले को स्थानांतरित नहीं किए जाने की अक्सर संभावना पर जमानत पर रिहा होने पर अभियुक्त के अधिकार को हतोत्साहित नहीं किया जा सकता है, या कि मजिस्ट्रेट गलती से एक आदेश पारित करने से इनकार कर देता है और मामले को उच्च मंच पर ले जाया जाता है और मध्यावधि में चालान दायर किया जाता है। अभियोजन पक्ष की ओर से निर्दिष्ट अवधि के भीतर चालान दायर करने में विफलता पर अभियुक्त के तथाकथित अक्षम्य अधिकार और अभियोजन एजेंसी की ओर से निष्क्रियता के कारण अभियुक्त को जमानत पर रिहा होने से कानूनी रूप से रोकने में बड़े पैमाने पर समाज के हित के बीच संतुलन बनाने का यही एकमात्र तरीका है।"

(27) इस प्रकार, यह देखा गया कि एक बार जब अभियुक्त को एक अक्षम्य अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो उसे अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने में जांच एजेंसी की बाद की कार्रवाई से निराश नहीं किया जा सकता है।हालाँकि, प्रज्ञा सिंह ठाकुर (उपरोक्त) के मामले में एक विसंगत ध्यान दें की गई थी, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ/बैंच ने कहा है कि यदि सांविधिक/चूक जमानत के लिए आवेदन दायर किया जाता है और उसी विचाराधीनता रहने के दौरान-चालान दायर किया जाता है, तो सांविधिक/चूक जमानत पर रिहा होने का उक्त अधिकार समाप्त हो जाएगा और फिर आरोपी को केवल गुण-दोष पर रिहा किया जा सकता है, न कि चूक से।यह उपरोक्त निर्णय है, जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का आधार है, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि यदि आवेदन और चालान एक ही तारीख को दायर किए गए थे, तो खंड 167 (2) Cr.P.C के तहत अभियुक्त का रिहा होने का अधिकार समाप्त हो जाएगा।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर (उपरोक्त) के मामले में फैसले पर ही मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार किया गया।

सी. बी. आई. बनाम निराला यादव @राजा राम मास्टर यादव @दीपक यादव (12) जिसमें यह देखा गया कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर (ऊपर) के मामले में निर्णय उदय मोहनलाल आचार्य (ऊपर) के मामले में न्यायधीश बैंच/बड़ी पीठ के फैसले के विपरीत चलता है और यह अभिनिर्धारित

किया गया कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर (ऊपर) के मामले में लिया गया दृष्टिकोण कानून के सही सिद्धांत को नहीं बताता है।

(28) इसलिए, यह स्पष्ट है कि आज की तारीख में कानून यह है कि एक बार जब आरोपी खंड 167 (2) Cr.P.C के तहत आवेदन करता है, तो इस तरह के आवेदन विचाराधीनता रहने के दौरान बाद के चरण में चालान दाखिल करके उसे निराश नहीं किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अब कानूनी रूप से अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर (उपरोक्त) के मामले में फैसले पर बहुत अधिक भरोसा करते हुए इसे प्रस्तुत किया गया था-जिसे बदले में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक विशिष्ट निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

इंडिया द्वारा (सुप्रा)।

(29) इसके अलावा, खंड 167 (2) Cr.P.C के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय क्या प्रासंगिक होगा, वह समय होगा जब आवेदन स्थानांतरित किया गया था और जिस समय चालान प्रस्तुत किया गया था, उस स्थिति में जब वे उसी तारीख को दायर किए गए थे।इस संबंध में, हमारे देश के कई उच्च न्यायालयों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भले ही खंड 167 (2) Cr.P.C के तहत आवेदन और चालान दोनों एक ही दिन प्रस्तुत किए जाते हैं-आरोपी रिहा होने का हकदार होगा यदि आवेदन पर समय से पहले विचार किया गया था। निम्नलिखित मामलों में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा उक्त दृष्टिकोण लिया गया हैः-

(i) के मामले में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय

गौसमोहिद्दीन बनाम राज्य (कर्नाटक), **2004 (2)** आरसीआर

(आपराधिक/criminal) 179 ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि Cr.P.C की खंड 167 (2) के तहत आरोप-पत्र और जमानत आवेदन एक ही दिन दायर किए जाते हैं; लेकिन, यदि जमानत आवेदन के बाद आरोप-पत्र दायर किया जाता है-तो Cr.P.C की खंड 167 (2) के तहत आरोपी का अधिकार समाप्त नहीं होगा।कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क इस प्रकार हैः-

“7. आई. डी. 1 की खंड 167 (2) के तहत अभियुक्त के जमानत पर रिहा होने के अधिकार को अक्षम्य बताते हुए उच्चतम न्यायालय के लगातार निर्णयों का कारण यह है कि यह अधिकार प्रकृति में अनिवार्य है और कोई विकल्प नहीं है

(12) 2014 (3) आर. सी. आर. (सी. आर. एल/Crl.) 534

अगर वह जमानत देता है, अदालत में छोड़ दिया लेकिन आरोपी को जमानत पर रिहा करने के लिए संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को एक मूल्यवान अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है जिसे केवल कानून के प्रावधानों के अनुसार और अनुरूप ही वंचित किया जा सकता है।आई. डी. 1 की खंड 167 (2) के परंतुक के खंड (ए) के तहत पुलिस हिरासत के अलावा हिरासत में आरोपी को हिरासत में रखने की मजिस्ट्रेट की शक्ति उसमें निर्धारित अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाती है।परिणामस्वरूप अभियुक्त के पक्ष में जमानत पर रिहा होने का अधिकार प्राप्त होता है और यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि जाँच एजेंसी आरोप पत्र दाखिल नहीं करती।इसलिए, निर्धारित अवधि के भीतर जांच पूरी करने में जांच एजेंसी द्वारा चूक के कारण जमानत पर रिहा होने के लिए आरोपी के पक्ष में जो अधिकार प्राप्त होता है, वह केवल तभी समाप्त हो जाता है जब आरोपी के समक्ष आरोप पत्र दायर किया जाता है, जो खंड 167 (2) के तहत अधिकार का लाभ उठाता है। जब कोई आरोपी अपने अक्षम्य अधिकार को लागू करने के लिए जमानत के लिए आवेदन दायर करता है और वह आरोप पत्र दायर करने से पहले निर्देश दिए जाने पर जमानत देने के लिए तैयार होता है, तो आरोपी ने अपने अक्षम्य अधिकार का लाभ उठाया है, भले ही अदालत ने अभी तक जमानत के लिए अपने आवेदन का निर्धारण नहीं किया है।इसलिए, जहां उसी दिन आरोप पत्र दायर किया जाता है, यदि यह जमानत के लिए आवेदन के समय के बाद होता है, तो अभियुक्त के लिए उपलब्ध अक्षम्य अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है।"

((ii) गुजरात से पहले भी इसी तरह का एक तथ्यात्मक मैट्रिक्स सामने आया था।

उच्च न्यायालय ने आलमखान उमरखान जटमलेक जेनजारी ताल, दशदा जिला, सुरेंद्रनगर बनाम गुजरात राज्य, 2015 (46) आर. सी. आर. (आपराधिक) 801 के मामले में, जिसमें

वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन Cr.P.C की खंड 167 (2) के तहत 10.11.2014 पर 10.30 AM पर स्थानांतरित किया गया था। हालाँकि, उसी तारीख को, यानी 10.11.2014 पर, आरोप पत्र भी दाखिल किया जाने लगा, हालांकि शाम 4 बजे।गुजरात उच्च न्यायालय, संघ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार करने के बाद

सी. बी. आई. बनाम निराला यादव @राजा राम यादव @दीपक यादव (ऊपर)

द्वारा से भारत ने माना कि

बाद में चालान दाखिल करना, भले ही उसी दिन हो, लेकिन बाद में, यानी 4 :00 बजे ,वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा होने के आरोपी के अधिकार को समाप्त नहीं करेगा। उक्त निर्णय के प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

“14. चूंकि सीमा की अवधि 90 दिन है जो 09.11.2014 पर समाप्त हो गई है, इसलिए अगली तारीख यानी 10.11.2014 पर 10 बजेः35 सुबह में, आवेदकों पूर्वाहन एक आवेदन दायर किया।हालाँकि, संबंधित न्यायालय द्वारा उस पर तुरंत कोई आदेश पारित नहीं किया गया और अंततः 4 बजेः00 शाम को आरोप-पत्र दाखिल होने लगा।मेरे विचार में, हालांकि उक्त आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, फिर भी, अभियुक्त व्यक्तियों ने सुबह 10 बजे आवेदन दायर करके जमानत पर रिहा होने के अपने अधिकार का प्रयोग कियाः35 ए. एम., क्योंकि उस समय भी उनकी नजरबंदी को गैरकानूनी कहा जा सकता था।मेरे विचार में, शाम को 4 बजे आरोप-पत्र दाखिल करने से स्थिति नहीं बचेगी।मैं सी. बी. आई. बनाम सी. बी. आई. द्वारा से भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को दोहरा सकता हूं।निराला यादव @राजा राम यादव @दीपक यादव (ऊपर) ने कहा कि विलंब विधायी जनादेश को हतोत्साहित करता है।एक अदालत एक अभियुक्त के अधिकार को समाप्त करने के लिए कार्य नहीं कर सकती है यदि कानून उसे ऐसा प्रदान करता है।कानून की जीत होनी चाहिए।उदय मोहनलाल (ऊपर) में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द "तुरंत" है।"तुरंत" शब्द के सादा शब्दकोश अर्थ का अर्थ है तुरंत।यदि ऐसा है, तो संबंधित न्यायालय का कर्तव्य है कि वह तुरंत आवश्यक आदेश पारित करे, विशेष रूप से जब जमानत आवेदन में अधीक्षक द्वारा 10 तक का समर्थन किया गया थाः35 सुबह आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया। अदालत को तुरंत लोक अभियोजक को बुलाना चाहिए था, हालांकि, ऐसा करने के बजाय, उसने गलती से नोटिस जारी किया और अगले दिन यानी 11.11.2014 पर सुनवाई तय की।”

(iii) कि दीपक मंडल के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही इसी तरह का विचार लिया जा चुका है।

दीपू मंडल @छोटू बनाम झारखंड राज्य, **2015 (18)** आर. सी. आर. (आपराधिक) **433** के साथ-साथ मध्य प्रदेश

गणेश प्रसाद बनाम के मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय

एम. पी. राज्य, 2001 (4) आर. सी. आर. (आपराधिक/Crl.) 669।

(30) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, ऊपर (घ) के रूप में तैयार किए गए चौथे प्रश्न का उत्तर यह है कि यदि Cr.P.C की खंड 167 (2) के तहत आवेदन के साथ-साथ चालान, दोनों एक ही दिन दायर किए जाते हैं-यह देखना होगा कि क्या आवेदन चालान के लिए समय से पहले दायर किया गया था। यदि यह पाया जाता है कि आवेदन वास्तव में समय से पहले दायर किया गया था, भले ही उसी दिन-अभियुक्त का वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा होने का अक्षम्य अधिकार बरकरार रहेगा।

(31) अंत में, इस न्यायालय के विचार के लिए जो प्रश्न अंततः उठा वह यह है कि क्या वर्तमान मामले में 90 दिनों की अवधि उस समय समाप्त हो गई थी जब खंड 167 (2) के तहत आवेदन दायर किया गया था ताकि वर्तमान अपीलकर्ता को वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा होने का अधिकार मिल सके। अपीलकर्ता और जाँच एजेंसी दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा इस बात पर विवाद नहीं किया गया है कि अभियुक्त को07.11.2017 पर गिरफ्तार किया गया था और सी. बी. आई. द्वारा 08.11.2017 पर किशोर न्यायाधीश बोर्ड के समक्ष पेश किया गया था। इस संबंध में, वर्तमान अपील के पैराग्राफ संख्या 5 में इस आशय का स्पष्ट कथन किया गया है, जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

“5. कि सी. बी. आई. द्वारा मामले के पुनः पंजीकरण के बाद, याचिकाकर्ता को 07.11.2017 पर गिरफ्तार किया गया था और 08.11.2017 पर सी. बी. आई. द्वारा किशोर न्यायाधीश बोर्ड के समक्ष पेश किया गया था और तब से वह हिरासत/अवलोकन गृह में है।”

(32) इसी तरह, सी. बी. आई. की ओर से दायर शपथ पत्र में भी, सी. बी. आई. द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि कानून के साथ टकराव में बच्चे को आई. डी. 1 पर गिरफ्तार किया गया था और 08.11.2017 पर किशोर न्यायाधीश बोर्ड के समक्ष पेश किया गया था। यह स्वीकार किया गया है कि 08.11.2017 पर, आरोपी को 08.11.2017 से 11.11.2017 तक तीन दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। इस हद तक प्रासंगिक अभिकथन सी. बी. आई. द्वारा शपथ पत्र के पैराग्राफ Nos.3 और 6 में किए गए हैं, जिन्हें निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

“3. 07.11.2017 पर सी. बी. आई. इस निष्कर्ष पर पहुंची कि भोलू याचिकाकर्ता (एल.

डी. द्वारा दिया गया काल्पनिक नाम) की संलिप्तता की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। ट्रायल कोर्ट), विद्यालय का 11 वीं कक्षा का छात्र, विद्यालय में लड़कों के वॉशरूम में 7 साल के बच्चे की हत्या के मामले में 08.09.2017 पर चाकू से बच्चे का गला काटकर। इसलिए, कानून के साथ संघर्ष में किशोर को उसके पिता श्री विनोद कुमार राघव को आशंका के आधार और उसके खिलाफ लगाए गए, आशंका यह थी कि आरोपों को समझाने के बाद एक जघन्य अपराध करने के लिए 07.11.2017 उसका पिता, पुलिस थाना लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली के कल्याण पुलिस अधिकारी, सीबीआई के कल्याण अधिकारी और दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में गिरफ्तार किया गया था।

6. वह भोलू एल. डी. में बनाया गया था। किशोर न्यायाधीश बोर्ड, गुरुग्राम ने 08.11.2017 पर उनकी पुलिस हिरासत के लिए आवेदन दिया।एल. डी. किशोर न्यायाधीश बोर्ड, जिला अदालतें, गुरुग्राम इस मामले के महत्व पर विचार करते हुए कि यह एक बहुत ही सनसनीखेज मामला है और जघन्य अपराध के दायरे में आता है, जिसमें विद्यालय के भूतल पर लड़के के शौचालय के अंदर एक 7 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, ने भोलू की 3 दिनों की पुलिस हिरासत 08.11.2017 से 11.11.2017 को विशिष्ट निर्देशों के साथ दी कि भोलू की जांच 10:00 सुबह से 06 बजेः00 के बीच की जानी चाहिए और उन्हें उक्त 3 दिनों के लिए सेवा कुटीर, किंग्सवे कैंप, नई दिल्ली में रखा जाना है। किशोर न्यायाधीश बोर्ड, गुरुग्राम, हरियाणा ने भी सुश्री ज्ञानवती, एल. डी. को निर्देश दिया। किशोर न्यायाधीश बोर्ड, गुरुग्राम के सदस्य पुलिस हिरासत की अवधि के दौरान सी. बी. आई. द्वारा भोलू से पूछताछ के समय किशोर के साथ उपस्थित रहेंगे।"

(33) इस प्रकार, यह रिकॉर्ड पर सामने आया है कि आरोपी को 07.11.2017 पर गिरफ्तार किया गया था और 08.11.2017 पर किशोर न्यायाधीश बोर्ड के सामने पेश किया गया था-जहाँ से उसे तीन दिन की पुलिस रिमांड के लिए भेज दिया गया था।अभिलेख पर यह भी सामने आया है कि नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार, इस प्रभाव से कि विचाराधीन चालान 05.02.2018 पर दायर किया गया था। इस प्रकार, संक्षिप्त प्रश्न, जिस पर विचार किया जाना है, वह यह है कि क्या अभियुक्त 90 दिनों की अवधि के लिए हिरासत में रहा या नहीं।माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के अनुसार 90 दिनों की अवधि की गणना करते समय, जिस दिन आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, उसे बाहर रखा जाना चाहिए।रिलायंस को चगंती के मामले में

पहले के फैसलों पर रखा गया था.

सत्यनारायण और अन्य बनाम ए. पी. 14 का राज्य और राज्य के मामले में

एम. पी. बनाम रुस्तम और अन्य 15 का यह निष्कर्ष निकालना कि 90 दिनों की अवधि की गणना अभियुक्त की रिमांड की तारीख से की जानी है, न कि गिरफ्तारी की तारीख से। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि जिस दिन रवि प्रकाश सिंह अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था जिसे बाहर रखा जाना चाहिए जबकि चालान दाखिल करने की तारीख को शामिल किया जाना चाहिए।

(34) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, ऊपर (ई) के रूप में तैयार किए गए अंतिम प्रश्न का उत्तर यह है कि खंड 167 (2) Cr.P.C के तहत वर्तमान अपीलकर्ता को कोई अक्षम्य अधिकार अर्जित नहीं हुआ है और अपीलकर्ता वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं था। (35) जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, तथ्यों और कानूनी स्थिति को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है क्योंकि खंड 167 (2) Cr.P.C के तहत उसे कोई अक्षम्य अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है और वर्तमान अपील किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण, इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

डॉ. पायल मेहता

13 2015 (2) आर. सी. आर. (सी. आर. एल.) 89

@अरविंद सिंह बनाम राज्य(13) के मामले में अदालत

14 1987 (1) आर. सी. आर. (क्रोरल) 40

15 1995 एससीसी (सी. आर. एल.) 830

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यन्वयन के उद्देश्य के लिए इसका उपयुक्त रहेगा ।

अनुवादक

गरिमा गिलानी